भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4405
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क

4405. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट परियोजना पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना या किसी अन्य समान पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र, संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और मध्य प्रदेश के अत्यंत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कार्य शुरू किया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इंटरनेट और तकनीकी साक्षरता बढ़ाने तथा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट पैकेजों के साथ-साथ इंटरनेट तक पहुँच को लोगों के लिए वहनीय बनाने हेतु लक्षित दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) देश भर की ग्राम पंचायतों (जीपी) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 30.06.2025 तक 2,14,325 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिनमें महाराष्ट्र की 24,575

ग्राम पंचायतें (जीपी), दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की 38 ग्राम पंचायतें (जीपी) और मध्य प्रदेश की 17,850 ग्राम पंचायतें (जीपी) शामिल हैं। शेष ग्राम पंचायतों (जीपी) और बिना ग्राम पंचायत वाले गाँवों को माँग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित सेवा से वंचित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से प्राप्त वित्त पोषण के माध्यम से 'भारतनेट' और विभिन्न मोबाइल परियोजनाएं शुरू की है। जून 2025 तक, डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4जी सेचुरेशन स्कीमों के तहत पूरे भारत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) वाले 2,574 गाँवों में कुल 21,748 मोबाइल टावर (महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंव दीव और मध्य प्रदेश के 3,804 टावर सहित) शुरू किए गए हैं।

(घ) सरकार ने डिजिटल अभिगम्यता और समावेशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल आरंभ की है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को ई-सेवाएँ प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भारतनेट उद्यमी मॉडल के तहत फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, देश भर में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं के प्रसार के लिए सरकार, प्रसार भारती और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****